गन्ना उत्पादों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण जदेना

654. श्री यादवेन्द्र दत्त :
श्री श्यामलाल ध्रुव :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना उत्पादकोंको राष्ट्रीकृत बैंकों के माध्यम से ऋण देने की योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उनको ऋण किन शर्तों पर दिया जाएगा और ऋण की अधिकतम सीमा क्या होगी;

(ग) योजना का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यन्वित किया जाएगा; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत कितने गन्ना उत्पादकों को ऋण दिये गये हैं तथा प्रत्येक को कितनी राशि का ऋण दिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह): (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से गन्ना उत्पादकों को ऋण दिये जाने की कोई योजना नहीं है। परन्तु राष्ट्रीयकृत बैंक प्रत्यक्ष रूप से अथवा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से अपने कृषि ऋणों के रूप में गन्ना उत्पादकों को वित्तीय सहायता दे रहे हैं। सामान्यतः वित्तपोषक बैंकों, गन्ना मिलों और पंजीकृत गन्ना उत्पादकों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता होता है जिसके अन्तर्गत उत्पादक-गण मिलों को गन्ना देने का वादा करते हैं और मिलें इन उत्पादकों को भुगतान की जाने वाली गन्ने की कीमतों में से बैंकों को देय राशि काटने तथा उस राशि को उस बैंक को भेजने को सहमत होती है जिसने उत्पादक को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की मात्रा का ब्यौरा और वित्तपोषित गन्ना उत्पादकों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

Income-tax concessions to Companies for Undertaking Rural Development Programme

655. SHRI NIHAR LASKAR:
SHRI R. V. SWAMINATHAN:
SHRI M. V. CHANDRASEKHARA MURTHY:

Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 78 companies have beeen allowed income-tax concessions for undertaking rural development programme;

(b) if so, what are the companies granted concessions so far;

(c) what are the rural programme that will be undertaken by these companies;

(d) to what extent they have started rural development programme and in which areas; and

(e) what is the check that will be kept by the Union Government on them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ZULFIQUARULLAH): (a) Till December, 1978, approval under Section 35CC of the Income Tax Act, 1961 was accorded to programme furnished by 78 companies.

(b) to (d). The number of companies whose programme have been approved so far under Section 35CC is 83. The names of the companies and particulars of the approved programme are given in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-3330/79]. Many of the companies have started implementing the approved programme but the details, however, would be available only when the claim for deduction of the expenditure incurred on the approved programme is made and examined at the time of the assessment of the income.

(e) In order to claim deduction of the expenditure incurred on the approved programme of rural development, the companies are required to furnish, along with the return of the income for the assessment year for which the deduction is claimed, a statement of such expenditure in the prescribed form.

Payment of Income-tax by Contractors Companies Operating in TISCO Group of Collieries

656. SHRI A. K. ROY: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE be pleased to state:

(a) names of the owners and shareholders of the contractor companies